भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 270
जिसका उत्तर मंगलवार 19 जुलाई, 2016 को दिया जाना है

विद्युत से चलने वाले वाहनों हेतु निधियां

270. श्री ए. टी. नाना पाटील:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत से चलने वाले वाहनों हेतु लिथियम बैटरियों के विनिर्माण के लिए कोई निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शत प्रतिशत विद्युत और हाइब्रिड मोबिलिटी की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग): भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन वर्ष 2011 में अनुमोदित किया और तत्पश्चात् राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का शुभारंभ 2013 में किया। इस मिशन के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने 01 अप्रैल, 2015 से फेम इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित की है। इस स्कीम को 2020 तक 6 वर्ष की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें नियत अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और इसके विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र को प्रोत्साहित करना अभीष्ट है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी वाहन सेगमेंटों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहन और बसों को प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम का उद्देश्य 2020 तक प्रत्येक वर्ष 6-7 मिलियन वाहनों को बाजार में लाए जाने के लक्ष्य के साथ लगभग 9500 मिलियन लीटर ईंधन की संचयी बचत करना है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2 मिलियन टन की कमी होगी।

****